भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1077

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में पीएमएमवाई की स्थिति

1077. श्री नारायण तातू राणे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने योजना का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुरुष और महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा पीएमएमवाई के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों और अन्य व्यावसायिक वर्गों के लिए उक्त योजना तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या त्वरित कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमलआई) द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में दिनांक 24.01.2025 तक प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की स्थिति नीचे दी गई है:

(राशि करोड़ रुपए में)

जिला	स्वीकृत किए गए ऋण खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
रत्नागिरी	2.46 लाख	2,591.61	2,487.60
सिंधुदुर्ग	1.70 लाख	1,779.05	1,706.81

(ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा पीएमएमवाई के अंतर्गत रोजगार सृजन का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया गया था। अध्ययन में इस पर प्रकाश डाला गया है कि 3 साल की अवधि के दौरान, वर्ष 2018 तक, मुद्रा योजना के कारण लगभग 1.12 करोड़ निवल अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ।

(ग): रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में महिला लाभार्थियों को स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	स्वीकृत ऋण खातों की कुल संख्या	(ख) में से महिलाओं को स्वीकृत ऋण खाते
(क)	**(ख)**	**(ग)**
रत्नागिरी	2.46 लाख	1.26 लाख
सिंधुदुर्ग	1.70 लाख	0.88 लाख

एमएमवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों के संबंध में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचार अभियान, आवेदन पत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, आबंटित लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि की निगरानी करने के लिए बैंकों के साथ, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर बार-बार समीक्षाएं आदि शामिल हैं।

जनसमर्थ पोर्टल और PSB Loans in 59 Minutes जैसे प्लेटफॉर्म आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन के साथ व्यक्तियों और कारोबारों के लिए ऋण प्राप्त करने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण आवेदनों की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिससे कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता कम हो गई है।

******